

कराना राज्य सरकार के बस की बात नहीं रही है। मैं भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से जोरदार मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को आर्थिक रूप से ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान की जाए ताकि राज्य सरकार जो यह नष्ट हुई फसलें, वृक्ष और गरीब लोगों की भूमि, मकान, सड़कें इत्यादि जो भी खराब हुई हैं, उनकी पूर्ति कर सके।

(iii) ALLEGED EXPLOITATION OF LABOURERS ENGAGED IN STONE QUARIES AND CRUSHERS BY CONTRACTORS

श्री बोलत राम सारण (चुरू) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन खान मजदूर भयंकर शोषण के शिकार के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

मेवला महाराजपुर जिसे गधा-खोर भी कहते हैं, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ लकड़पुर, अनंगपुर, सराय कटन क्षेत्र की पत्थर की खानों और वहां लगे क्रेशरों पर दस हजार से भी अधिक खान मजदूर काम करते हैं। इन खान मजदूरों का ठकेदार बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं।

ये खान मजदूर मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ठकेदारों द्वारा हरियाणा के हैं। इन हजारों मजदूरों को ठकेदार द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इनमें से अधिकांश स्थानीय भाषा हिन्दी नहीं समझते। इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, शुद्ध पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात का इकट्ठा हुआ गन्दा पानी पीते हैं, जिससे गैंग्जों मलेरिया आदि से बीमार हैं। इन्हें सस्ते भाव पर अनाज आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अन्तर्राज्यीय विस्थापित मजदूर अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि श्रमिकों के लाभ और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत इन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही कोई व्यवस्था है। इन हजारों मजदूरों का भयंकर शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। ये मजदूर केवल ठकेदारों के रहम पर जी रहे हैं।

इन हजारों मजदूरों की चिन्ताजनक स्थिति से इनकी रक्षा की जाए। इनका शोषण उत्पीड़न समाप्त किया जाए। ये खानें, मजदूरों को सहकारी समितियां बना कर उन्हें पट्टे पर दी जायें, उन्हें ही क्रेशर लगवा कर दिए जायें और ठकेदारी प्रथा समाप्त करके इनका शोषण समाप्त किया जाए।

आशा है सरकार का श्रम विभाग इस ओर ध्यान दे कर इन्हें राहत दिलाएगा।

(iv) ESTABLISHMENTS OF TWO MORE ATOMIC POWER UNITS TO SOLVE POWER CRISES IN RAJASTHAN

श्री० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : भारत में बिजली का संकट और अधिक बढ़ता जा रहा है इस से कृषि तथा लघु उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। राजस्थान की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक राजस्थान परमाणु बिजली घर 8 वर्ष से लगातार बीमार चल रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच चार बिजली परियोजनाओं में साझेदारी है। गांधी सागर और सतमुड़ा से मध्य प्रदेश राजस्थान को बिजली नहीं दे रहा है। इधर रावतमाटा परमाणु बिजली घर का यह रिकार्ड है कि नियमित रूप से 8 दिन भी लगातार यह नहीं चला। बार-बार इसके बन्द होने से कृषि तथा उद्योगों को भारी क्षति हुई है।

हमें स्वदेशी ईंधन तथा भारी पानी का उपयोग इस में हो सके ऐसी व्यवस्था